नए भारत की नई अयोध्या : पुनर्निर्माण की महागाथा

काल चक्र की गति विचित्र है। जो नगरी सदियों तक उपेक्षा, संघर्ष और विस्मृति के अंधकार में पड़ी रही, वही आज स्वर्णिम पुनर्जागरण की प्रतीक बनकर उभरी है। अयोध्या – रघुकुल की राजधानी, मर्यादापुरुषोत्तम की जन्मस्थली और सनातन संस्कृति का हृदय-केंद्र – आज केवल आस्था का तीर्थ नहीं, वरन् आधुनिक भारत की संरचनात्मक क्षमता और राष्ट्रीय संकल्प का जीवंत दर्पण बन चुकी है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ जो प्रज्वलित हुआ, उसकी रोशनी अब केवल धर्म के प्रांगण तक सीमित नहीं रही – वह समूचे नगर को, उसकी सड़कों को, उसके आकाश को और उसके भविष्य को आलोकित कर रही है। भारत की स्वाधीनता के अमृत-काल में अयोध्या का यह पुनर्निर्माण महज एक शहर के कायाकल्प की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत के आत्मविश्वास की घोषणा है जो अपनी जड़ों से जुड़ते हुए आकाश को छूने का स्वप्न देखता है।

संरचनात्मक विकास की दृष्टि से अयोध्या का रूपांतरण अभूतपूर्व गति और परिमाण में हो रहा है। IIM लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के लिए कराए गए एक विशेष अध्ययन के अनुसार अयोध्या में लगभग 85,000 करोड़ की पुनर्विकास परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगतिशील हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2033 तक अयोध्या को विश्व के श्रेष्ठतम नगरों की पंक्ति में स्थापित किया जाए। यह केवल एक नारा नहीं, एक सुचिंतित और सुसंगठित विकास-दर्शन है जिसे विभिन्न प्रमुख विकास-बिंदुओं के इर्द-गिर्द बुना गया है – इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, सौंदर्यीकरण, पर्यटन और हरित विकास सब कुछ इस महाभियान का अंग है।

मंदिर निर्माण से पूर्व की अयोध्या और आज की अयोध्या के बीच की दूरी को मापा जाए तो संख्याएं ही सबसे सटीक भाषा बोलती हैं। IIM लखनऊ की जनवरी, 2026 की रिपोर्ट इस परिवर्तन को रेखांकित करती है। मंदिर-पूर्व काल में अयोध्या में वार्षिक श्रद्धालुओं की संख्या मात्र 1.7 लाख के इर्द-गिर्द रहती थी, स्थानीय दुकानदारों की औसत दैनिक आय ?400 से ?500 तक सीमित थी, राष्ट्रीय स्तर की होटल श्रृंखलाओं की उपस्थिति नगण्य थी और हवाई संपर्क का सर्वथा अभाव था। वर्ष 2024 में प्राण-प्रतिष्ठा के उपरांत प्रथम छः माह में ही 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024 में अयोध्या में कुल 16 करोड़ 44 लाख से अधिक श्रद्धालु आए, जो 2023 की तुलना में लगभग तीन गुना था। और वर्ष 2025 की बात करें तो जनवरी से जून 2025 के मध्य ही यह संख्या 23 करोड़ 82 लाख का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर गई – यह संख्या अपने आप में किसी भी तर्क की अपेक्षा नहीं रखती।

इस विशाल जन-प्रवाह को सहजता से वहन करने हेतु अयोध्या की परिवहन-संरचना का कायाकल्प सबसे पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। 6,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में फैले इस टर्मिनल भवन की वार्षिक यात्री-क्षमता लगभग 10 लाख है और इसकी वास्तुकला स्वयं राम मंदिर की शैली से अनुप्राणित है – टर्मिनल के अग्रभाग में मंदिर की वास्तुशिल्प छवि उकेरी गई है, तो आंतरिक दीवारें रामायण के प्रसंगों को दर्शाने वाले भित्तिचित्रों से सज्जित हैं। यह हवाई अड्डा GRIHA पांच-सितारा मानकों पर निर्मित है, जिसमें वर्षा-जल संचयन, सौर ऊर्जा संयंत्र और LED प्रकाश-व्यवस्था जैसी हरित प्रौद्योगिकियों का समावेश किया गया है। इसी प्रकार अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी उतनी ही सूक्ष्मता और भव्यता से हुआ है। लगभग 10,000 वर्गमीटर में विकसित किए जा रहे इस स्टेशन भवन को राम मंदिर की स्थापत्य शैली में ही निर्मित किया गया है। अत्याधुनिक यात्री-सुविधाओं, तीन नए प्लेटफार्मों, आकर्षक भवन-संरचना और सुव्यवस्थित पार्किंग से युक्त यह स्टेशन भवन देश के सर्वाधिक सुंदर रेलवे स्टेशनों में गणना योग्य है। और यह भी उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है – इस दूरी को इलेक्ट्रिक बसों और ई-रिक्शा से सहज जोड़ा गया है।

सड़क और नगर-नियोजन के क्षेत्र में अयोध्या का परिवर्तन और भी व्यापक है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और जन्मभूमि पथ जैसे चौड़े, सुसज्जित और हरित मार्गों ने नगर के हृदय को खोल दिया है। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण, अयोध्या बाईपास (रिंग रोड) का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बस स्टेशन का विकास – ये सब मिलकर उस संपर्क-जाल की बुनावट करते हैं जो लाखों तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाता है। नगर में 36 मीटर चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड यूटिलिटी नेटवर्क और ग्रीन-ब्लू कॉरिडोर के निर्माण की योजनाएं भी प्रगति पर हैं। नई अयोध्या केवल भूतकाल की भव्यता का स्मारक नहीं बनना चाहती – वह 21वीं सदी की एक संपूर्ण नगरी बनने की आकांक्षा रखती है।

इस समग्र दृष्टि का सबसे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प है अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप, जिसे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद संचालित कर रही है। राम जन्मभूमि मंदिर से मात्र 4.5 किलोमीटर दूर, NH-27 बायपास के निकट सरयू तट पर स्थित इस परियोजना का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 1,407 एकड़ है, जिसमें से 720 एकड़ भूमि पर भौतिक कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस टाउनशिप में हरित क्षेत्र, कृत्रिम झीलें, वेलनेस हब, हाईटेक पार्क, सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सेंटर और 300 से अधिक आवासीय भूखंड – सब कुछ एकीकृत रूप से नियोजित है। 'नव्य अयोध्या' की इस अवधारणा में सौर ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन और पर्यावरण-संरक्षण को केंद्रीय स्थान दिया गया है। यह टाउनशिप अयोध्या को एक 'मॉडल सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने के व्यापक विजन का अंग है। गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट तक 10 किलोमीटर की लंबाई में विश्व की सबसे लंबी सौर स्ट्रीट-लाइट परियोजना के अंतर्गत 400 से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं – यह तथ्य अपने-आप में अयोध्या की हरित दृष्टि का प्रमाण है।

सरयू नदी और उसके तटों का पुनरुद्धार इस महायज्ञ का एक और महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। सूर्यकुंड और भरतकुंड जैसे प्राचीन जलाशयों का पुनर्जीवन हो रहा है। घाटों का सौंदर्यीकरण, नदी-तट की पक्की पगडंडियाँ, रात्रि-प्रकाश की सुव्यवस्था और दीपोत्सव जैसे भव्य आयोजनों ने सरयू-तट को एक जीवंत सांस्कृतिक स्थल में बदल दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का 'मास्टर प्लान 2031' इस विकास को दीर्घकालिक संस्थागत ढाँचे में बाँधता है। 'वेदिक सिटी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स' (VCSI) जैसे नवाचार इस बात के प्रमाण हैं कि अयोध्या का पुनर्निर्माण केवल ईंट-पत्थर का खेल नहीं, एक सोची-समझी सतत-विकास की यात्रा है।

इस संरचनात्मक उत्थान का आर्थिक प्रभाव उतना ही व्यापक है। द्वुद्वरूलखनऊ के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश में पर्यटन व्यय ?4 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें अयोध्या की भूमिका केंद्रीय है। पर्यटन-आधारित गतिविधियों से कर-राजस्व ?20,000 से ?25,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ताज होटल्स, मैरियट इंटरनेशनल और विंडहैम होटल्स जैसी अंतरराष्ट्रीय आतिथ्य श्रृंखलाओं ने अयोध्या में अपने विस्तार की घोषणाएं कर दी हैं। 150 से अधिक नए होटल और होमस्टे पहले ही स्थापित हो चुके हैं। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों पर अयोध्या की बुकिंग में चार गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के आकलन के अनुसार मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर देशभर में 1 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ, जिसमें अयोध्या की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही। अयोध्या में प्रतिदिन दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन स्थानीय व्यापार, परिवहन, हस्तशिल्प और सेवा-क्षेत्र को नित नई ऊर्जा दे रहा है।

अयोध्या का यह पुनर्निर्माण एक ऐसे भारत का प्रतिबिंब है जो अपनी सांस्कृतिक स्मृति को आर्थिक शक्ति में रूपांतरित करना जानता है। यह नगरी अब केवल भूतकाल की गाथा नहीं गाती – वह भविष्य की भाषा बोलती है। मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम का संदेश था कि धर्म और व्यवस्था, आस्था और न्याय, परंपरा और प्रगति – सब एक साथ संभव हैं। नई अयोध्या इसी संदेश का स्थापत्य-रूपांतरण है। ?85,000 करोड़ की परियोजनाएं, 23 करोड़ से अधिक वार्षिक श्रद्धालु, विश्वस्तरीय हवाई अड्डा, स्मार्ट टाउनशिप और सौर ऊर्जा से जगमगाते घाट – ये सब मिलकर उस नई अयोध्या की रूपरेखा खींचते हैं जिसे नया भारत गर्व से देख सकता है, जिस पर विश्व अचंभित होकर दृष्टि टिका सकता है। रामराज्य की कल्पना केवल एक आदर्श नहीं थी – वह एक कार्यसूची थी। और आज, उस कार्यसूची के पन्ने एक-एक कर पलटे जा रहे हैं।

डॉ. शैलेश शुक्ला
वैश्विक समूह संपादक
सृजन संसार अंतरराष्ट्रीय पत्रिका समूह
आशियाना, लखनऊ – 226012, उत्तर प्रदेश

देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक है भ्रष्टाचार

भारत एक ऐसा देश है जिसने हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति को अपने भीतर समेटा है। यह वही धरती है जहाँ 'सत्यमेव जयते' को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। लेकिन स्वतंत्रता के सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, इस राष्ट्र की प्रगति की गाथा में एक काला अध्याय लगातार जोड़ा जाता रहा है – और वह है भ्रष्टाचार। यह केवल किसी एक विभाग या व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसी महामारी बन चुकी है जो राष्ट्र की जड़ों को भीतर से खोखला करती जा रही है। भ्रष्टाचार का अर्थ है सत्ता, पद या संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग। यह घूसखोरी से लेकर सरकारी धन के गबन तक, भाई-भतीजावाद से लेकर सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े तक फैला हुआ है। जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी उचित काम के लिए भी रिश्वत माँगता है, जब सरकारी ठेके योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि चंदे और सिफारिश के आधार पर मिलते हैं, जब न्यायिक प्रक्रिया को पैसे की ताकत से प्रभावित किया जाता है – तो ये सब भ्रष्टाचार के ही विविध रूप हैं।

भ्रष्टाचार की वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति : ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रतिवर्ष 'भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' जारी करती है जिसमें 180 देशों को उनके यहाँ भ्रष्टाचार की स्थिति के आधार पर स्थान दिया जाता है। वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा और उसे 100 में से केवल 39 अंक मिले। यह स्थिति बताती है कि हम सुधार की दिशा में अभी काफी पीछे हैं। देश के भीतर कैग (CAG - Comptroller and Auditor General of India) की विभिन्न रिपोर्टें समय-समय पर सरकारी खर्चों में भारी अनियमितताओं का पर्दाफाश करती रही हैं। 2त्न स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला – ये कुछ ऐसे मामले हैं जो हजारों करोड़ रुपये के सार्वजनिक नुकसान से जुड़े रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2त्न मामले में खुद कहा था कि यह देश के संसाधनों की 'राष्ट्रीय क्षति' थी।

विकास पर भ्रष्टाचार का सीधा प्रभाव : विश्व बैंक के अनेक अध्ययनों में यह सिद्ध किया गया है कि भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास के बीच एक उलटा संबंध है – जहाँ भ्रष्टाचार अधिक है, वहाँ दीर्घकालीन विकास दर कम रहती है। जब सरकारी परियोजनाओं की लागत भ्रष्टाचार के कारण बढ़ जाती है, तो सीमित राष्ट्रीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा बेकार हो जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि जितने स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बाँध बनने चाहिए थे, वे नहीं बन पाते। नीति आयोग और विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्टें यह दर्शाती रही हैं कि ग्रामीण विकास से जुड़ी कल्याण योजनाओं का बड़ा हिस्सा लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँचता। मनरेगा, पीडीएस, आवास योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों की संख्या और 'बिचौलियों' की भूमिका चर्चा का विषय रही है। यानी गरीबों के लिए बनाई गई योजनाएँ उन तक पूरी तरह नहीं पहुँच पातीं।

बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का असर साफ दिखता है। सड़कें बनने के कुछ महीनों में ही टूटने लगती हैं क्योंकि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होता है। भवन निर्माण में नियमों की अनदेखी होती है जिसके कारण इमारतें भूकंप या बाढ़ में ढह जाती हैं और जानमाल की भारी क्षति होती है। इन सबके पीछे वह भ्रष्ट तंत्र है जो नियमों की अनदेखी करने के लिए धन लेता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार : शिक्षा किसी भी राष्ट्र की नींव होती है। लेकिन जब शिक्षक नियुक्ति में घूस माँगी जाती है, जब परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, जब डिग्रियाँ खरीदी और बेची जाती हैं – तो पूरी शैक्षिक व्यवस्था की साख गिर जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में समय-समय पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक और फर्जी डिग्री के मामले सामने आते रहे हैं जिनकी जाँच सीबीआई तक पहुँची है। ऐसे में जो मेधावी छात्र ईमानदारी से पढ़ते हैं, उन्हें उनका उचित अवसर नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार और भी घातक है क्योंकि यहाँ जीवन-मृत्यु का प्रश्न जुड़ा होता है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ बाहर से खरीदवाना, फर्जी दवा खरीद, घटिया उपकरणों की खरीद – ये समस्याएँ देश के कोने-कोने में दिखती हैं। COVID-19 महामारी के दौरान कई राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर और पीपीई किट खरीद में अनियमितताओं की खबरें आईं, जो उस संकट के समय और भी अमानवीय थीं।

न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र पर असर : लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था होती है। यदि इन दोनों में भ्रष्टाचार घर कर जाए तो पूरे तंत्र की नींव हिल जाती है। पुलिस में भ्रष्टाचार सबसे आम शिकायतों में से एक है। एफआईआर न दर्ज करना, जाँच को प्रभावित करना, आरोपियों को बचाना – ये समस्याएँ कमजोर और शक्तिहीन नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती हैं। प्रशासनिक स्तर पर भू-अभिलेख, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे रोजमर्रा के कामों में भी नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है और उनसे अवैध धन वसूला जाता है। इससे जनता का सरकारी तंत्र पर से भरोसा उठने लगता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है।

भ्रष्टाचार के सामाजिक और नैतिक दुष्प्रभाव : भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान नहीं करता, यह समाज के नैतिक ताने-बाने को भी नष्ट करता है। जब कोई बच्चा देखता है कि बेईमानी से सफलता मिलती है, तो उसके मन में ईमानदारी के प्रति आस्था कमजोर होती है। जब समाज में यह संदेश जाता है कि 'पैसे से सब कुछ होता है', तो सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा खोखली पड़ जाती है। भ्रष्टाचार के कारण ही देश की प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा विदेश की ओर पलायन करता है। जब मेरिट के बजाय पैसे और सिफारिश से नौकरियाँ मिलती हैं, तो प्रतिभाशाली लोगों को अपने ही देश में उचित अवसर नहीं मिलते। इसे 'ब्रेन ड्रेन' कहते हैं और यह दीर्घकाल में राष्ट्र की सबसे बड़ी बौद्धिक हानि है।

भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास और उनकी सीमाएँ : देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), लोकायुक्त संस्थाएँ, सीबीआई और ईडी – ये सब इस दिशा में काम करने के लिए बनाए गए हैं। जनवरी 2014 में दिल्ली में स्थापित और बाद में 2019 में पूरे देश में लागू हुए लोकपाल का गठन भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम था। 2005 में लागू सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) ने आम नागरिकों को एक शक्तिशाली हथियार दिया। इसके जरिए जनता सरकारी कामकाज की जानकारी माँग सकती है जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरटीआई का उपयोग करके बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। हालाँकि यह भी दुखद है कि अनेक आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियाँ मिली हैं और कुछ की जान भी गई है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने से भी भ्रष्टाचार में कुछ हद तक कमी आई है। जब नागरिक घर बैठे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आय-जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं तो बिचौलिए की भूमिका कम होती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में भेजने से भी मध्यस्थों द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। परंतु इन सभी प्रयासों की अपनी सीमाएँ हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाएँ स्वयं यदि भ्रष्टाचार से मुक्त न हों, तो वे कारगर नहीं हो सकतीं। जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता का प्रश्न हमेशा से विवाद का विषय रहा है। राजनीतिक संरक्षण में होने वाला भ्रष्टाचार सबसे कठिन चुनौती है क्योंकि उसे कानूनी जकड़न में लाना बेहद मुश्किल होता है।

समाधान की दिशा में विचार : भ्रष्टाचार एक बहुआयामी समस्या है इसलिए इसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। सबसे पहली जरूरत है – शिक्षा में नैतिकता का समावेश। यदि बचपन से ही ईमानदारी, जवाबदेही और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को बच्चों में बोया जाए तो आने वाली पीढ़ी अधिक भ्रष्टाचार-मुक्त होगी। महात्मा गाँधी ने कहा था – 'भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं।' दूसरी आवश्यकता है – जाँच एजेंसियों की वास्तविक स्वायत्तता। यदि सीबीआई, ईडी और अन्य जाँच एजेंसियाँ राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त हों और उन्हें संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त हो, तो वे निष्पक्ष जाँच कर सकेंगी। न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को कम करना भी जरूरी है ताकि भ्रष्ट व्यक्ति को शीघ्र सजा मिले और 'देरी से न्याय' का लाभ नहीं उठाया जा सके। तीसरी दिशा है – चुनाव सुधार। चुनावों में काले धन का बोलबाला भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ों में से एक है। जब नेता चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तो सत्ता में आने के बाद उस पैसे की 'भरपाई' का दबाव भी बनता है। चुनाव खर्च की पारदर्शी निगरानी, राज्य-वित्त पोषित चुनाव और उम्मीदवारों की संपत्ति-घोषणा की सख्त जाँच – ये कदम जरूरी हैं। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है – नागरिक जागरूकता और सामाजिक दबाव। जब तक समाज यह स्वीकार करता रहेगा कि 'यह तो यहाँ चलता है' या 'सब तरफ यही है', तब तक भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी होती रहेंगी। जब नागरिक रिश्वत देने से इनकार करेंगे, शिकायत दर्ज कराने का साहस दिखाएँगे और भ्रष्ट लोगों को वोट देने से परहेज करेंगे – तभी असली बदलाव आएगा।

उपसंहार : भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक इसलिए नहीं है कि यह केवल धन की बर्बादी करता है – बल्कि इसलिए कि यह उस विश्वास को तोड़ता है जिस पर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र टिका होता है। जब नागरिक अपनी सरकार पर, संस्थाओं पर और व्यवस्था पर से भरोसा खो देते हैं, तो विकास की कोई भी योजना अपना पूरा फल नहीं दे सकती। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था – 'यदि एक देश भ्रष्टाचार-मुक्त होना चाहता है और सुंदर मनों का राष्ट्र बनना चाहता है, तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि समाज में तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य यह कर सकते हैं – पिता, माता और शिक्षक।' यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भ्रष्टाचार केवल कानून से नहीं, बल्कि चरित्र-निर्माण से मिटेगा। भारत की युवा पीढ़ी के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है। एक ऐसा भारत बनाना जहाँ 'सत्यमेव जयते' केवल मुद्रा पर नहीं, बल्कि हर नागरिक के आचरण में उतरे – यही असली विकास होगा। और यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि न भ्रष्टाचार करूँगा, न करने दूँगा।

– डॉ. शैलेश शुक्ला
वैश्विक समूह संपादक
सृजन संसार अंतरराष्ट्रीय पत्रिका समूह
आशियाना, लखनऊ – 226012, उत्तर प्रदेश
मो. : 9312053330, 8759411563

हंगामा लोक सामाजिक,साहित्य समिति द्वारा किया गया सकल जैन समाज को सम्मानित

धामपुर (बिजनौर) हंगामा लोक सामाजिक,साहित्य समिति के संरक्षक डॉ जितेन्द्र कौशिक निर्मला कौशिक समिति की संस्थापिका राखी कौशिक उपासना कौशिक समिति के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा ,समिति के संगठन मंत्री डॉ राजमोहन विश्वास ,तारा जोशी आदि समिति के सदस्यों द्वारा सकल जैन समाज को सम्मानपत्र भेट कर सनातन सारथी सम्मान से सम्मानित किया व साथ ही सकल जैन समाज द्वारा निकाली गयी स्वर्ण रथ यात्रा का हंगामा लोक साहित्यिक व सामाजिक समिति की संस्थापिका राखी कौशिक उपासना कौशिक समिति के संरक्षक डा. जितेंद्र कौशिक, निर्मला कौशिक, समिति के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा,संगठन मंत्री डॉ राजमोहन विश्वास ,तारा जोशी,आशा गोस्वामी आदि द्वारा पुष्प वर्षा व प्रसाद वितरण कर भव्य स्वागत किया गया। हंगामा लोक सामाजिक,साहित्य समिति को ट्रस्ट श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर द्वारा 141 वाँ स्वर्ण रथयात्रा महामहोत्सव पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

आज़ाद महोत्सव : काव्य-हस्ताक्षर - श्याम सिंह शेखावत

राष्ट्रव्यापी पंजीकृत साहित्यिक संस्था आज़ाद कलम ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज़ाद महोत्सव के विराट कवि सम्मेलन में ग्राम लुहाकना खुर्द, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान से पधारे कवि श्याम सिंह शेखावत ने सामाजिक चेतना और प्रेरक ओज से परिपूर्ण प्रस्तुति द्वारा विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर उनका व्यक्तित्व दृढ़, आत्मविश्वासी और जनजागरण की स्पष्ट प्रतिबद्धता से युक्त दिखाई दिया।

उनकी रचनाधर्मिता का मूल स्वर संघर्षशीलता, आत्मबल और सकारात्मक परिवर्तन की चेतना है। वे परिस्थितियों से समझौते के बजाय उनसे टकराने का संदेश देते हैं। उनकी कविता केवल प्रेरक उद्घोष नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि का सशक्त प्रतिपादन है, जिसमें कर्म, साहस और आशा का संतुलित संगम

उपस्थित रहता है।

श्याम सिंह शेखावत की भाषा सरल, ओजस्वी और सीधी है, पर प्रभाव अत्यंत गहरा छोड़ती है। वे श्रोताओं को भावुकता में नहीं बहाते, बल्कि उन्हें भीतर से जाग्रत करने का प्रयास करते हैं। उनकी प्रस्तुति में आत्मविश्वास की स्वाभाविक लय और विचार की स्पष्टता विशेष रूप से अनुभव की गई।

मंच से प्रस्तुत उनकी पंक्तियाँ-

'हार हो या जीत हो तू ना कभी
भयभीत हो,
टकरा तू हर मुसीबत से बस,
आशा तेरी मीत हो।
बन हथोड़ा तोड़ दे तू अपनी राह
का हर प्रस्तर,
जला हृदय में दीप ज्योति,
अंधकार को प्रकाश कर।
नाश कर तू नाश कर, चाहे फिर
विनाश कर। '

इनमें संघर्ष का संकल्प, आत्मविश्वास का उभार और परिवर्तन की तीव्र चेतना स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होती है।

आज़ाद महोत्सव के मंच पर उनका यह काव्य-पाठ सामाजिक जागरण, साहस और कर्मप्रधान दृष्टि का प्रभावी काव्य-हस्ताक्षर सिद्ध हुआ। इस अवसर पर उन्हें 'आज़ाद साहित्य श्री सम्मान' से सम्मानित किया गया।

– धर्मेन्द्र कुमार धर्मी दौसा, राजस्थान